



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 कार्तिक 1937 (श0)

(सं0 पटना 1233) पटना, सोमवार, 26 अक्टूबर 2015

सं0 कारा/नि0को0(क)-17/2012-6285  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग

संकल्प

13 अक्टूबर 2015

श्री देवेन्द्र प्रसाद, काराधीक्षक, सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध उनके मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन अवधि के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, लापरवाही, कर्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक विफलता के लिए निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12 दिनांक 24.02.2012 धारा-420/409/ 467/468/471/120 बी0 भा.द.वि. के अन्तर्गत एवं 13 (2) सहपठित धारा-13 (1) सी.डी. भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 दर्ज है। उक्त घटना के लिए श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-187 दिनांक 11.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोशी प्रमण्डल, सहरसा नामित किए गए।

2. निगरानी विभाग द्वारा घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गये कर्मियों/भ्रष्टाचार/वित्तीय अनियमितता एवं गबन से संबंधित मामलों की समीक्षापरान्त श्री प्रसाद को उक्त घटना तथा उनके मंडल कारा किशनगंज में पदस्थापन के दौरान जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों यथा कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुर्व्यवहार, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना संबंधी आरोपों के लिए उन्हें विभागीय संकल्प ज्ञापांक 673 दिनांक 05.02.2014 द्वारा निलंबित किया गया।

3. श्री प्रसाद के विरुद्ध मंडल कारा, किशनगंज के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित पूरक आरोप पत्र को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 843 दिनांक 13.02.2014 द्वारा पूर्व से संस्थित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए पूरक आरोप पत्र पर भी जांच कर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध गठित सभी 13 मूल एवं 6 पूरक आरोपों को प्रमाणित पाया गया। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 4847 दिनांक 05.09.2014 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई एवं स्मार पत्र भी निर्गत किया गया। श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में उल्लेख किया गया कि कारा के अन्दर प्रशासनिक कठोरता बरते जाने के कारण कक्षपाल यूनियन के एक सदस्य ब्रजेश कुमार, कक्षपाल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन देकर उन पर अनर्गल आरोप लगाया गया, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। इसके अतिरिक्त एस.एल.आर. एवं गोलियाँ पुलिस लाईन में रखने का आदेश

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज द्वारा दिया गया, जो इसके लिए सक्षम पदाधिकारी नहीं है। साथ ही यह भी अंकित किया गया कि कक्षपाल, श्री ब्रजेश कुमार के द्वारा दिये गये आवेदन पर विभागीय अनुशंसा के उपरांत निगरानी न्यायालय में दर्ज वाद संख्या-26/12 प्रक्रियाधीन है। अतः न्यायिक प्रक्रिया तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। श्री प्रसाद के अनुसार संचालन पदाधिकारी द्वारा न तो स्थल निरीक्षण किया गया एवं न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी का भौतिक परीक्षण ही किया गया है। अतः जांच प्रतिवेदन को ही जांच के घेरे में होने का मत व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही की जांच किसी वरीय अथवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से कराने का अनुरोध किया है।

5. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर, उनके विरुद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी का अधिगम एवं संचिका में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की सम्यक् समीक्षा से स्पष्ट होता है कि अपने अभ्यावेदन में श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही संस्थित किए जाने के आदेश को रद्द करते हुए नया संचालन पदाधिकारी नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है जो अप्रासंगिक एवं नियमसंगत नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि श्री प्रसाद ने अपने विरुद्ध गठित आरोपों का बिंदुवार कोई उत्तर नहीं दिया है, अपितु विभागीय कार्यवाही संस्थित किए जाने संबंधी सरकार के संकल्प को ही गलत कहते हुए उसे रद्द करने का अनुरोध किया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

6. संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध मूल आरोप पत्र में गठित कुल 13 आरोप तथा पूरक आरोप पत्र में गठित कुल 6 आरोप, सभी प्रमाणित पाए गए हैं जिसके आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री प्रसाद के विरुद्ध गठित सभी आरोप उनके द्वारा पद के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता, सरकारी राशि के गबन आदि से संबंधित हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद का अनुरोध प्रासंगिक एवं नियमसंगत नहीं है और अविचारणीय है।

7. यह भी स्पष्ट है कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में उनके विरुद्ध प्रक्रियाधीन न्यायिक मामला बाधक नहीं हो सकता, जबतक कि संबंधित न्यायालय द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश निर्गत न किया गया हो। इस प्रकार श्री प्रसाद का संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समर्पित उत्तर तथ्यहीन एवं अप्रासंगिक कथनों तथा नियमसंगत अनुरोध नहीं करने के आलोक में स्वीकारयोग्य नहीं है।

8. उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षोपरांत अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/किशनगंज, सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के प्रावधानों के तहत “सेवा से बर्खास्तगी” का दंड निरूपित करने का विनिश्चय किया गया।

9. उपर्युक्त विनिश्चित दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 1113 दिनांक 19.02.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गई। इसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1096 दिनांक 17.07.2015 द्वारा प्रस्तावित दंड से सहमति व्यक्त की गई है। प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक् विश्लेषणोपरांत श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा/किशनगंज (सम्प्रति निलंबित) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के तहत निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है:-

“सेवा से बर्खास्तगी का दंड।”

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री देवेन्द्र प्रसाद (बिहार कारा सेवा) सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ) एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव वर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1233-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>